राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–prrajbhavan@gmail.com
मो॰–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राजभवन में कुलसचिवों एवं वित्त पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पटना, 31 मई 2018

आज राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं वित्त पदाधिकारियों की एक बैठक हुई; जिसमें विश्वविद्यालयों की गतिविधियों एवं उच्च शिक्षा के सुधार–प्रयासों हेतु निर्धारित एजेन्डे के अनुरूप कार्य–प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि विकास–प्रयासों की दिशा में अगर हम प्रत्येक महीने थोड़ी–थोड़ी उपलब्धि भी हासिल करते हैं, तो हम व्यापक सुधार करने में कामयाब हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने सेवांत लाभ, नियमित एवं बकाये वेतन–भुगतान आदि पर कुलपतियों की बैठक में बहुत जोर दिया है; अतएव इस दिशा में ठोस पहल हर हालत में सुनिश्चित की जानी है प्रधान सचिव ने प्रत्येक माह 'पेंशन अदालत' लगाते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया।

प्रधान सचिव ने कहा कि लंबित न्यायालयीय वादों के निष्पादन के क्रम में भी पूरी तत्परता और सजगता आवश्यक है।

प्रधान सचिव ने बी॰एड॰ में नामांकन हेतु आयोजित होनेवाली 'राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा' की तैयारियों में भरपूर सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि बी॰एड॰ कॉलेजों के गहन निरीक्षण के लिए भी ठोस व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले तो इन कॉलेजों का प्रारंभिक 'डाटाबेस' तैयार किया जाएगा, फिर 'नये एप्स' के जरिये इन कॉलेजों से नियमित सूचनाएँ संग्रहित की जाएँगी। उन्होंने कहा कि इनके क्लास रूम, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्टाफ रूम आदि की सूचनाएँ 'सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम' के जरिये तस्वीरों एवं सांख्यिकी के रूप में प्राप्त की जाएँगी, ताकि इन कॉलेजों में नियमित अध्यापन सुनिश्चित हो सके। प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु बी॰एड॰ कॉलेजों में नियमित अध्यापन की व्यवस्था निहायत जरूरी है।

बैठक में कुलसचिवों को बायोमैट्रिक प्रणाली के जरिये प्राप्त सूचनाओं के संकलन एवं उनके आलोक में आवश्यक कार्रवाई को अंतिम परिणति तक पहुँचाने को कहा गया। साथ ही महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक कैलेण्डर के अनुरूप प्रतियोगिताएँ आयोजित करने तथा 'विशेष स्वच्छता अभियान' भी संचालित कराने हेतु भी उन्हें ताकीद किया गया। 'Government e-Marketplace (GeM)' के माध्यम से खरीददारी करने एवं आर॰टी॰जी॰एस॰ के तहत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों के बैंक–खातों की इंटरलिंकिंग कराने आदि विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई।

बैठक में अपर सचिव श्री विजय कुमार सहित राज्यपाल सचिवालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

.....